RNI No#MPBIL/2013/49052

# INVESTMENT AVENUES®

# इन्वेस्टमेंट ऐवेन्यूस

भोपाल, शनिवार 22 नवंबर से 28 नवंबर 2025 | भोपाल , मध्यप्रदेश से प्रकाशित | वर्ष- 13 | अंक-67 | पृष्ठ- 8 | मूल्य- रु. 5 /-

## जैक्सन ग्रुप ने मध्य प्रदेश में 8,000 करोड़ का सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट शुरू किया

### 6 GW एकीकृत प्लांट से आत्मनिर्भर भारत को बल, 4,000 नौकरियां सृजित; मक्सी में चरणबद्ध विस्तार, मई 2026 तक मॉड्यूल उत्पादन

**भोपाल:** जैक्सन ग्रुप ने मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के मक्सी फेज-2 औद्योगिक क्षेत्र में 8,000 करोड़ रुपये के निवेश से 6 GW एकीकृत सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की शुरुआत की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भूमिपूजन किया। यह भारत का सबसे बड़ा सोलर उत्पादन केंद्र होगा, जो इंगॉट, वाफर्स, सेल्स और मॉड्यूल्स का पूर्ण उत्पादन करेगा।

ग्रुप के चेयरमैन समीर गुप्ता ने कहा, यह प्लांट भारत के केंद्र से तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा और स्वच्छ ऊर्जा क्षमता बढ़ाएगा। प्रोजेक्ट दो चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में 2,000 करोड़ के निवेश से 3 GW सेल्स और 4 GW मॉड्यूल्स क्षमता बनेगी। मई 2026 तक पहला मॉड्यूल रोल आउट होगा, उसके बाद सितंबर में सेल्स। दूसरे चरण में 6,000 करोड़ से 6 GW वाफर्स के साथ अतिरिक्त 3 GW मॉड्यूल्स और सेल्स क्षमता जोड़ी जाएगी।कुल 110 एकड़ में फैला यह प्लांट तीन वर्षों में 4,000 नौकरियां सृजित करेगा।

जैक्सन इंजीनियर्स के जॉइंट MD और CEO गगन चनाना ने कहा, हमारा 'फोर-इन-वन' मॉडल—मैन्युफैक्चरर, डेवलपर, EPC और O&M गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। मध्य प्रदेश का चयन केंद्रीय स्थान, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रगतिशील नवीकरणीय नीतियों के कारण हुआ। यह PLI स्कीम के तहत है, जो भारत के 500 GW नॉन-फॉसिल लक्ष्य को गति देगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सोलर निर्यात बढ़ेगा। जैक्सन सोलर के पास पहले से 1.2 GW मॉड्यूल क्षमता है। शेयर बाजार में जैक्सन के शेयर 2.5% चढ़े। यह कदम 'आत्मनिर्भर भारत' को मजबूत करेगा।

## FDI-FII प्रवाह को गति देने पर पीयूष गोयल की हितधारकों से बैठक: प्रक्रिया को तेज, सरल बनाने पर जोर

### वाणिज्य मंत्रालय में चर्चा, निवेशक समुदाय से सुझाव; अमेरिका के साथ व्यापार सौदे की प्रगति के बीच नीतिगत स्थिरता पर फोकस

**नई दिल्ली:** वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को वाणिज्य मंत्रालय के वाणिज्य भवन में हितधारकों के साथ बैठक की, जिसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और विदेशी संस्थागत निवेश (FII) को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा हुई। गोयल ने कहा, निवेश प्रक्रिया को तेज, सरल और कुशल बनाने के लिए हम लगातार परामर्श कर रहे हैं। यह बैठक निवेशक समुदाय से सुझाव लेने का मंच थी, जहां FDI और FII दोनों को आसान बनाने पर फोकस रहा।

FICCI के 98वें वार्षिक आम सभा के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए गोयल ने कहा कि निवेश से रोजगार सृजन, नई तकनीकों, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने नीतिगत स्थिरता, स्थिर मुद्रा और निवेश पारिस्थितिकी तंत्र में विश्वास पर जोर दिया। हमें निवेशक समुदाय से पूछना चाहिए कि FDI और FII को कैसे तेज और अधिक कुशल बनाया जाए, गोयल ने कहा।

सरकार FDI और FII प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए निरंतर परामर्श कर रही है। अप्रैल-जून 2025 में FDI 15% बढ़कर 18.62 अरब डॉलर रहा। FY24 में FDI इक्विटी प्रवाह 50.01 अरब डॉलर और कुल FDI 80.6 अरब डॉलर था। गोयल ने उद्योगों से आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण और एक भूगोल पर निर्भरता कम करने का सुझाव दिया। उन्होंने भारत को घरेलू औद्योगिक विनिर्माण केंद्र बनाने पर जोर दिया, जिसमें आत्मनिर्भरता, गुणवत्ता उत्पाद, युवाओं को सशक्तिकरण, निवेश-अनुकूल पारिस्थितिकी और उन्नत तकनीक अपनाना शामिल है।

वाणिज्य मंत्री ने कहा कि निवेश रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देंगे, घरेलू मुद्रा को स्थिर रखेंगे और मुद्रास्फीति को कम करेंगे। बैठक में ई-कॉमर्स, स्टार्टअप और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विशेषज्ञों का मानना है कि ये परामर्श भारत को वैश्विक निवेश का केंद्र बनाएंगे।

## खजुराहो में ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस का उद्घाटन: मध्य प्रदेश को मिला नया लग्जरी हेरिटेज डेस्टिनेशन

### मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया शुभारंभ, 50 कमरों वाला पैलेस होटल; विश्व धरोहर स्थल पर पर्यटन को मिलेगी नई ऊंचाई

**खजुराहो:** मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को खजुराहो में द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस का भव्य उद्घाटन किया। 50 कमरों वाला यह अल्ट्रा-लग्जरी हेरिटेज होटल खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर समूह से महज कुछ मिनट की दूरी पर स्थित है और अब विश्व धरोहर स्थल के पर्यटन परिदृश्य में नया अध्याय जोड़ रहा है।

ओबेरॉय ग्रुप के चेयरमैन एमेरिटस पी.आर.एस. ओबेरॉय की स्मृति में समर्पित इस पैलेस को 1920 के दशक के राजगढ़ पैलेस को पुनर्स्थापित कर तैयार किया गया है। होटल में बुंदेली वास्तुकला का अनोखा संगम है, जिसमें आधुनिक सुविधाएं और ओबेरॉय की विश्व प्रसिद्ध आतिथ्य शैली शामिल है।

उद्घाटन समारोह में डॉ. यादव ने कहा, खजुराहो पहले से ही विश्व पर्यटन मानचित्र पर है। ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस जैसे लग्जरी हेरिटेज होटल से हाई-एंड पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि होगी और स्थानीय कारीगरों-शिल्पकारों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को GDP का 10% तक ले जाने के लिए लग्जरी और हेरिटेज सेगमेंट पर विशेष ध्यान दे रही है।

होटल में 42 डीलक्स रूम, 6 लग्जरी सूट और 2 प्रेसिडेंशियल सूट हैं। रेस्तरां बुंदेलखंड के शाही व्यंजनों के साथ विश्वस्तरीय भोजन परोसेंगे। पर्यटन विभाग के अनुसार, खजुराहो में विदेशी पर्यटकों की संख्या पिछले वर्ष 2.5 लाख पार कर चुकी है। इस नए पैलेस से 2026 तक 30% और वृद्धि की उम्मीद है।

# स्वास्थ्य बीमा लागत पर नियंत्रण: सरकार ला रही सख्त नियम, प्रीमियम कैप पर विचार

## मेडिकल इन्फ्लेशन 11.5% तक पहुंचने का अनुमान, IRDAI को भेजे सुझाव; अस्पतालों-बीमा कंपनियों से लागत कम करने की अपील

**नई दिल्ली:** स्वास्थ्य बीमा प्रीमियमों की बढ़ती लागत को नियंत्रित करने के लिए सरकार सक्रिय हो गई है। वित्त मंत्रालय ने बीमा कंपनियों, अस्पताल प्रतिनिधियों और उद्योग संगठनों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य बीमा लागत पर प्रतिबंध लगाने और खुलासा मानदंडों को कठोर बनाने के सुझाव दिए गए। एओन की ग्लोबल मेडिकल ट्रेंड रेट्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत में मेडिकल इन्फ्लेशन 2026 में 11.5% तक पहुंच सकता है, जो वैश्विक औसत 9.8% से अधिक है।

बैठक में वित्त मंत्रालय ने बीमा नियामक IRDAI को प्रीमियम कैप, एजेंट कमीशन सीमा और सख्त खुलासा नियमों के प्रस्ताव भेजे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हम अस्पतालों और बीमा कंपनियों से लागत कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। क्लेम सेटलमेंट और प्रीमियम निर्धारण में अनियमितताओं को रोकने के लिए हस्तक्षेप जरूरी है।" IRDAI चेयरमैन अजय सेठ ने पहले कहा था कि वे सेटलमेंट राशियों पर नजर रख रहे हैं।

यह कदम स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र की बढ़ती असमानताओं को संबोधित करता है, जहां प्रीमियम 20-30% सालाना बढ़ रहे हैं। सरकार कैशलेस क्लेम्स को तेज करने और नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज का एकीकरण बढ़ाने पर जोर दे रही है। FICCI और CII जैसे संगठनों ने समर्थन किया, लेकिन छोटी कंपनियों ने कमीशन कटौती पर चिंता जताई।

विशेषज्ञों का मानना है कि ये उपाय मध्यम वर्ग के लिए बीमा को सस्ता बनाएंगे। FY26 बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 90,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। यह कदम 'आयुष्मान भारत' योजना को मजबूत करेगा, जो 50 करोड़ लोगों को कवर करती है। स्वास्थ्य मंत्रालय और फार्मा विभाग भी मेडिकल डिवाइस पर मूल्य नियंत्रण पर विचार कर रहे हैं।

इससे उपभोक्ता संरक्षण बढ़ेगा, लेकिन उद्योग पर दबाव पड़ेगा।

# Digital Gold Platforms Urge SEBI Oversight: 'Regulate Us' to BuildInvestor Trust

## IBJA Letter Highlights Industry's Call for Framework After SEBI Warning; Backed by BIS-Approved Refiners, Firms Eye SRO if Regulator Declines

**Mumbai:** Amid regulatory ambiguity, digital gold companies are knocking on the Securities and Exchange Board of India (SEBI)'s door, seeking formal supervision to assure investors of safety and transparency. The India Bullion & Jewellers Association (IBJA) has written to SEBI Chairman Tuhin Kanta Pandey, urging the markets regulator to bring these platforms under its ambit or designate another authority, as reported by The Economic Times on November 18. This plea follows SEBI's November 8 advisory cautioning investors that digital gold products fall outside its jurisdiction, neither classified as securities nor regulated as commodity derivatives.

IBJA National Secretary Surendra Mehta revealed that several digital gold providers, including those backed by BIS and NABL-accredited refiners, have approached the body expressing willingness for regulation. "This oversight would dispel fears of misleading consumers and enhance credibility," Mehta told ET. Platforms like Tanishq (via Safe Gold) and MMTC-PAMP offer investments starting at ₹1, but lack SEBI's investor protections, prompting a surge in withdrawals post-advisory.

The request comes as digital gold holdings hit 25 tonnes in FY25, projected to double by FY30 per Technopak Advisors. If SEBI declines, firms may seek self-regulation via a Self-Regulatory Organisation (SRO) by November-end or approach the Ministry of Finance or Corporate Affairs, sources indicated. Experts like Sidharth Kumar of BTG Advaya endorse an SRO model akin to AMFI for mutual funds.

SEBI recommends regulated alternatives like Gold ETFs or Electronic Gold Receipts (EGRs) for liquidity and safeguards. With GST, storage fees, and platform charges adding to costs, regulation could standardize the ₹50,000 crore market, foster growth while mitigating risks like default or KYC lapses. As young investors flock to fractional ownership sans locker hassles, this push signals maturity in India's gold fintech ecosystem.

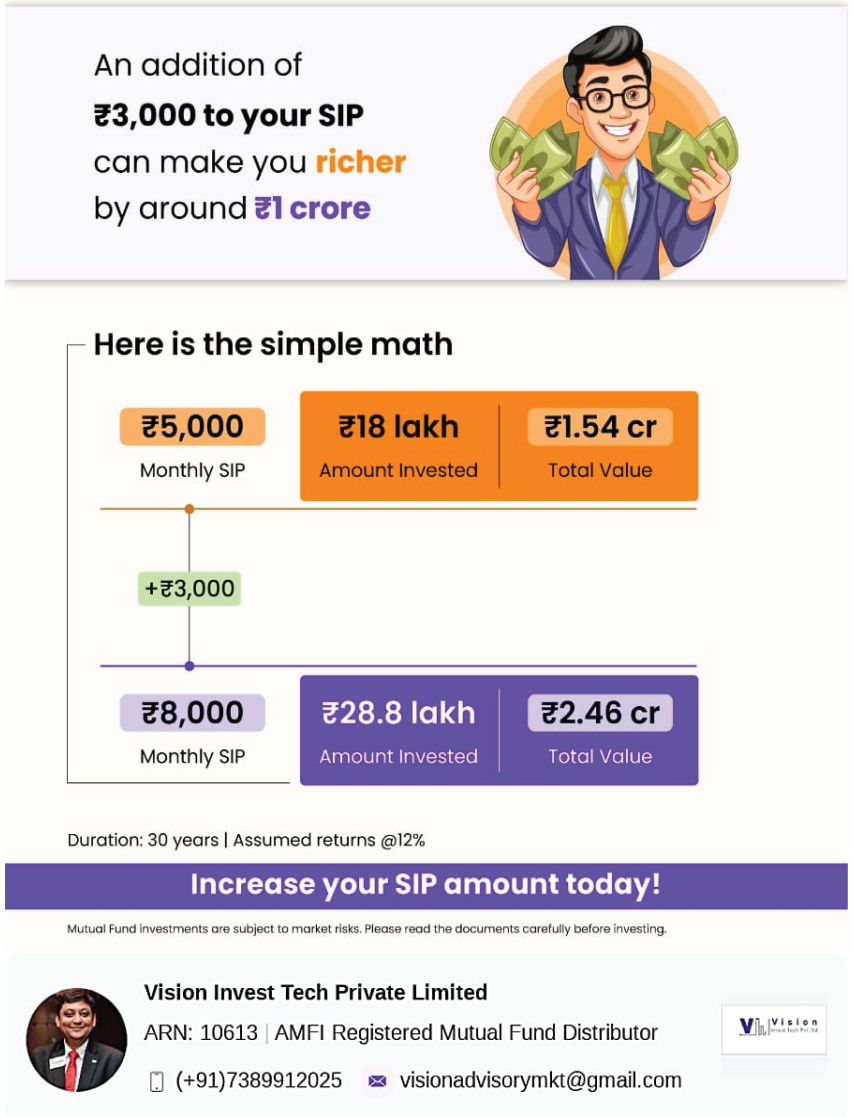

*Sh. Pradeep Karambelkar*
*Founder & Editor*

*Dr. Irshad Ahmad Khan*
*Sub-Editor*

*Sh. Pushpendra Singh*
*Marketing Officer*

# India's Defence, Infra & Railways ETFs: Riding the Economic Boom

## "When a nation builds roads, railways, and defence strength, it is not just building assets: it is building its future"

India is witnessing one of the biggest economic transformations in its history. Government spending on infrastructure, defence, and railways has increased massively, and this is creating new opportunities for investors. One of the simplest ways to participate in this growth is through ETFs (Exchange Traded Funds) that track these booming sectors.

In simple words, ETFs are baskets of stocks that you can buy like a single share. They allow you to invest in many companies together, without needing to pick each stock. This helps reduce risk and makes investing easier for beginners.

**Why are these Sector ETFs becoming popular?**

India's development story is no longer limited to metros, it is now reaching small towns, rural markets, and industrial hubs. To support this growth, the government is investing heavily in railway modernisation, defence manufacturing, and nationwide infrastructure building. As a result, companies in these sectors are seeing strong order books, rising profits, and long-term visibility.

Because of this, Defence ETFs, Infra ETFs, and Railways ETFs are attracting both new and experienced investors.

**1. Defence ETFs: India's move toward Self-Reliance**

The Indian defence sector is transforming rapidly. India is reducing imports and focusing on 'Make in India' weapons, aircraft, drones, and naval systems. Key drivers include:

• Exporting weapons to other countries
•Indigenous fighter jets, missiles, and naval ships
• Large government orders for defence PSUs
• Focus on national security and technological upgrades

Defence ETFs allow investors to benefit from the growth of leading companies without selecting each stock individually.

As India becomes a global defence exporter, this sector is expected to grow strongly in the next decade.

**2. Infra ETFs: Building the India of 2047**

Infrastructure is the backbone of any developed economy. India is building expressways, airports, smart cities, bridges, and logistics parks at record speed. Major growth reasons:

• Fastest highway construction globally
• ₹10 lakh crore+ annual infrastructure budget
• Strong push for logistics and smart urban development
• Private and global investments flowing into India

Infra ETFs capture the performance of construction, cement, energy, and engineering companies that are directly contributing to this massive development wave.

**3. Railways ETFs: The New Growth Engine**

Indian Railways is undergoing its biggest upgrade ever. From Vande Bharat, freight corridors, and bullet trains to modern stations and safer tracks: the entire system is being rebuilt. Why Railways ETFs are booming:

• Multiyear government investment
• Higher freight income and operational efficiency
• Growth in manufacturing of coaches, signalling, and tracks
• Increased role of private players

Railways-focused ETFs include companies that supply engines, wheels, electrical parts, and technological systems, a sector expected to grow steadily for the next 20–25 years.

**Why ETFs are the Smart Way to Invest in these Sectors**

• You don't need to pick individual stocks
• Lower cost compared to mutual funds
• Diversification reduces risk
• Easy to buy and sell like a normal share
• Suitable for both beginners and long-term investors

**Final Thought:**

India is entering a golden era of development. The boom in defence, infrastructure, and railways is not temporary- it is part of a long-term national vision for a developed India by 2047.

**"When the nation grows, your investments grow with it. ETFs are the simplest bridge between India's progress and your prosperity."**

*Dr. Irshad Ahmod Khan*
*Sub-Editor*

# अमेरिकी प्रतिबंधों से रूसी तेल पर संकट: भारत मध्य पूर्व से जहाज बुक कर रहा, आपूर्ति में तेजी

## 21 नवंबर की डेडलाइन से पहले रिफाइनर सतर्क, सऊदी-कुवैत से दर्जन भर टैंकर; आयात 66% गिरा, दिसंबर में वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भरता

**नई दिल्ली:** अमेरिकी प्रतिबंधों की 21 नवंबर की डेडलाइन से पहले भारत रूसी तेल आयात पर ब्रेक लगाने को मजबूर हो गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिफाइनर सऊदी अरब, कुवैत, इराक और UAE से दर्जन भर तेल टैंकर बुक कर रहे हैं, जो नवंबर के अंत से दिसंबर तक लोडिंग के लिए हैं। यह संख्या पिछले महीने के चार टैंकरों से दोगुनी है, जो रूसी आपूर्ति में कमी का संकेत है।

रूस के प्रमुख उत्पादक रोसनेफ्ट और लुकोइल पर लगने वाले प्रतिबंधों से भारत का रूसी तेल आयात प्रभावित होगा, जो कुल आयात का 36% है। केपलर डेटा के अनुसार, नवंबर में रूसी तेल शिपमेंट 66% गिरकर 6,72,000 बैरल प्रतिदिन रह गया, जो अक्टूबर के 18,80,000 बैरल से काफी कम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी और रोसनेफ्ट से जुड़ी नायरा एनर्जी की वादिनार पोर्ट पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा।

ट्रेडर्स के अनुसार, रूसी तेल के जहाज भारत पहुंचने से पहले डिस्चार्ज अनिश्चित है। IOC, HPCL और BPCL जैसी कंपनियां मध्य पूर्वी तेल पर निर्भरता बढ़ा रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि दिसंबर में रूसी आयात 50% घट सकता है, जिससे तेल कीमतें बढ़ेंगी।

रूस से आयात अप्रैल-सितंबर में औसतन 17,50,000 बैरल प्रतिदिन रहा। अमेरिकी दबाव से भारत वैकल्पिक स्रोत तलाश रहा है। यह बदलाव वैश्विक तेल बाजार को प्रभावित करेगा।

# Volkswagen Trims India EV Costs by 30%, Scouts Local Partners to Revive Market Share

## Platform Development Budget Slashed to $700M from $1B; Talks with JSW, Tata, Mahindra Amid 2027 Emission Norms and 2028 Launch Target

**Mumbai:** Volkswagen AG is aggressively cutting electric vehicle (EV) development costs in India by nearly one-third while intensifying its search for a domestic partner to bolster its stagnant market presence, according to sources familiar with the matter. The German automaker has reduced its platform investment to about $700 million from an initial $1 billion, signaling a strategic recalibration to navigate rising expenses and regulatory pressures in one of the world's fastest-growing auto markets.

The cost trims come as Volkswagen grapples with a mere 2% share after two decades in India, where EV adoption is accelerating ahead of stricter carbon-emission norms effective 2027.

With a dedicated EV launch slated for 2028, the company is prioritizing partnerships to share risks and funding, especially after failed talks with Mahindra & Mahindra last year. Skoda Auto Volkswagen India, the local arm, is in advanced discussions with potential allies including JSW Group a partner to China's SAIC Motor and Tata Motors, as well as an unnamed Indian contract manufacturer

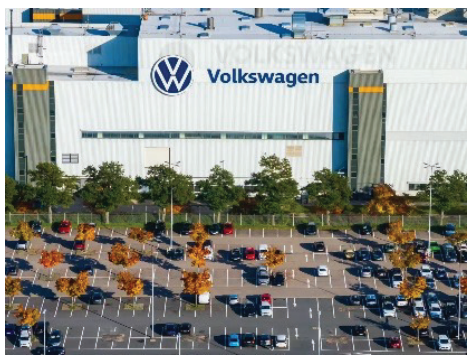


."Volkswagen is unwilling to shoulder billions alone in a high-risk market," a source told Bloomberg. The revised budget focuses on a tailored EV platform for affordable models, potentially including imports as a stopgap if the EU-India trade deal materializes. Talks aim to unlock internal approvals, with a deal eyed by mid-2026.

India's EV market, projected to hit 10 million units annually by 2030, offers Volkswagen a lifeline, but competition from Tata, Mahindra, and Hyundai looms large. The move aligns with global shifts, as VW reallocates resources amid US-China tensions. Shares of Volkswagen dipped 0.8% in Frankfurt, while Indian auto stocks rose on partnership buzz. As emission deadlines approach, this hunt could redefine VW's Indian playbook, blending cost prudence with collaborative innovation.

NFO Alert

PGIM India Mutual Fund

PGIM India Multi Asset Allocation Fund

(An open-ended scheme investing in equity and equity-related instruments, debt and money market instruments, Gold ETFs, and Silver ETFs)

**Fund Objective:**

To generate long-term capital appreciation by investing in multiple asset classes including equity and equity-related securities, debt and money market instruments, Gold ETFs, and Silver ETFs.

NFO PERIOD | November 11, 2025 November 25, 2025

*There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved
Mutual Fund investment is subject to market risks. Please read the documents carefully before investing.

Vision Invest Tech Private Limited
ARN: 10613 | AMFI Registered Mutual Fund Distributor
(+91)7389912025 visionadvisorymkt@gmail.com

MPBIL/2013/49052
INVESTMENT AVENUES®
(इन्वेस्टमेंट एवेनयुस)
(A Publication of Vision Invest Tech Pvt. Ltd.)

INVESTMENT AVENUES
CALL FOR ARTICLES

Share Your Knowledge with INVESTMENT AVENUES

We invite individual, professionals, and entrepreneurs to contribute their expertise and experiences.

- STOCK MARKET
- MUTUAL FUNDS
- REAL ESTATE
- STARTUPS & ENTREPRENEURSHIP

Guidelines:

1. Article must be original
2. Submit in MS Word format
3. Length should not exceed 500 words

editor@investmentavenues.in

write with us, inspire others, and make your voice heard in the world of investments!

# Inox Wind & KP Energy Join Forces for 2.5 GW Wind-Solar Hybrid

## Gujarat-Focused ISTS Projects to Be Delivered by FY28; Partnership Leverages Inox's 4 GW Order Book and KP's 2 GW+ EPC Expertise

**Vijayanagar:** Inox Wind Limited (IWL) has signed a strategic framework agreement with KP Energy Limited to jointly develop 2.5 GW of inter-state transmission system (ISTS) connected wind-solar hybrid and wind projects across Gujarat and other states. The MoU, announced on Tuesday, combines IWL's manufacturing prowess and 4 GW order book with KP Energy's proven EPC execution track record of over 2 GW.

Under the pact, KP Energy will provide balance-of-plant (BoP) services, while Inox Wind will supply its latest 3.x MW WTGs and handle operations & maintenance. The portfolio is targeted

for completion by FY28, with phased commissioning starting FY26. Gujarat, with its abundant wind-solar corridors, will be the primary focus, followed by Rajasthan and Karnataka.

This partnership is a perfect synergy, said Kailash Tarachandani, CEO of Inox Wind. We bring cutting-edge turbines and a strong order pipeline, while KP Energy's local execution strength ensures faster project turnaround. Faruk G. Patel, Chairman & MD of KP Energy, added, The collaboration allows us to scale rapidly in the hybrid segment, where India needs 50 GW+ capacity by 2030.

Both companies are already executing 1 GW+ of joint orders. Inox Wind's order book stands at 3.9 GW, with recent wins from C&I players and PSUs. Shares of Inox Wind rose 4.8% to Rs 198 and KP Energy surged 7% to Rs 512 on the BSE. Analysts see the tie-up as a game-changer for cost-effective hybrid delivery, reinforcing India's renewable energy ambitions.

# HAL-L&T's Historic PSLV Milestone: India's First Industry-Built Rocket Set for Oceansat Launch in Early 2026

## Consortium Delivers First PSLV-XL Hardware; ISRO's Shift to Private Production Marks New Era in Space Manufacturing

In a landmark achievement for India's space sector, the consortium of Hindustan Aeronautics Limited (HAL) and Larsen & Toubro (L&T) has successfully built the country's first industry-manufactured Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV), slated to launch the Oceansat satellite early next year. This development, announced in this week, signifies ISRO's strategic pivot toward private sector involvement in proven rocket production, freeing resources for cutting-edge missions.

The PSLV-XL hardware, delivered to ISRO's Sriharikota launch site, represents the initial output from a 2022 contract for five such vehicles. We have started delivering the PSLV hardware, and the first rocket built by the HAL-L&T consortium will launch the Oceansat satellite early next year, said a senior L&T executive. The Oceansat mission, part of ISRO's Earth observation program, will monitor ocean color, seasurface temperature, and wind vectors, aiding climate studies and disaster management.

Under the agreement, HAL and L&T handle end-to-end production, leveraging transferred technology from ISRO. This includes the vehicle's four stages: a solid-propellant first stage, liquid second stage, solid third, and liquid fourth. The PSLV, ISRO's workhorse with 62 launches (94% success rate as of May 2025), has deployed over 400 satellites globally.

The partnership aligns with ISRO's privatization drive, including tech transfer for the Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) to HAL. L&T's space arm, already executing 1 GW+ joint orders, eyes 10 more PSLV launches post these five. Experts hail it as a boost to 'Atmanirbhar Bharat' in space, potentially capturing 7% of the global market by 2030. Shares of L&T rose 2.1% to Rs 3,850 on BSE, reflecting optimism. As India targets 500 GW renewables and advanced missions, this collaboration propels self-reliance in rocketry.

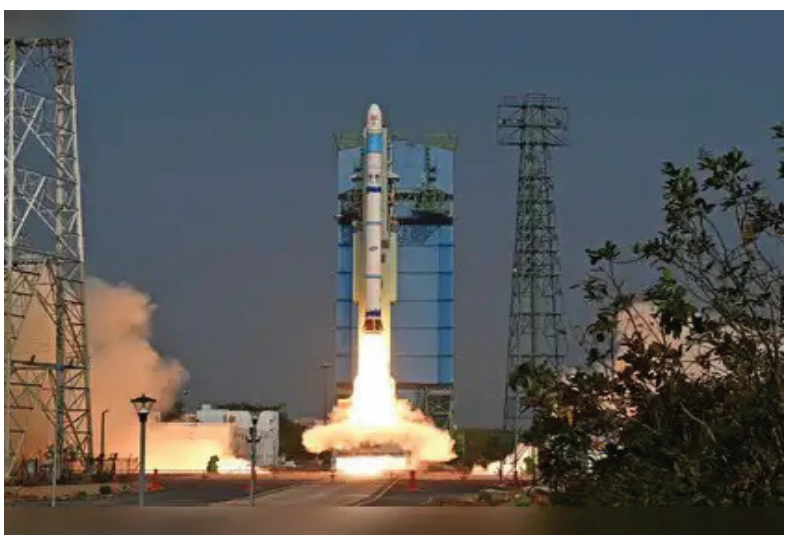

# Bajaj Auto Seals KTM Majority Stake Acquisition After Regulatory Greenlight

## €800M Debt Deal Completes Shift from Minority Partner to Controlling Owner; Rebranding and Global Expansion on Horizon

**Mumbai:** Bajaj Auto Ltd has finalized its long-awaited acquisition of a majority stake in Austrian motorcycle icon KTM AG, marking a transformative chapter for both companies. The deal, valued at €800 million (approximately Rs 7,765 crore), received final approval from European regulators on November 10, culminating in the transaction's closure on November 18, as announced in a BSE filing.

Through its wholly owned subsidiary Bajaj Auto International Holdings BV (BAIH), Bajaj acquired all 50,100 shares of Pierer Bajaj AG (PBAG) from Pierer Industrie AG (PIAG), securing full ownership of PBAG. This elevates Bajaj's effective stake in Pierer Mobility AG (PMAG)-KTM's holding company to 74.9%, up from a previous 37.5%. This consummates our controlling stake in PMAG and KTM, Bajaj stated,

rebranding PBAG as Bajaj Auto International Holdings AG and PMAG as Bajaj Mobility AG.

The move, first announced in May 2025, injects €600 million in fresh funding €450 million as a secured loan to KTM and €150 million in convertible bonds to revive the Austrian firm amid its restructuring. KTM, facing liquidity woes since November 2024, secured creditor approval in February 2025 for a 30% cash settlement by May 23, averting insolvency. Bajaj's infusion, including €200 million already committed, positions it as the sole majority owner, ending the Pierer Group's involvement.

Rajiv Bajaj, Managing Director, hailed it as a strategic evolution, leveraging Bajaj's manufacturing expertise and KTM's premium branding. With Bajaj's prior 48% stake in KTM since 2007, the partnership has birthed models like Dominar and Pulsar RS. Now, joint R&D and global exports aim to tap the $100 billion two-wheeler market.

Shares of Bajaj Auto surged 3.2% to Rs 9,850 on BSE, reflecting optimism. As India eyes 10 million EV two-wheelers by 2030, this alliance could redefine premium mobility, blending Indian scale with European flair.

# Godrej Properties Targets Rs 3,500 Cr from 30-Acre Bengaluru Township

## Godrej Forest Estate at Devanahalli to Launch in Q4 FY26; 3 million Sq Ft Premium Plotted Development to Capitalise on North Bengaluru Boom

**Bengaluru:** Godrej Properties Ltd (GPL) has set an ambitious revenue target of Rs 3,500 crore from its upcoming 30-acre premium plotted township, Godrej Forest Estate, located in the fast-growing Devanahalli-North Bengaluru corridor. The project, acquired through an outright purchase in July 2025, is slated for launch in the last quarter of FY26, company executives confirmed during the Q2 earnings call.

Spread across 30 acres, the development will offer approximately 3 million sq ft of saleable area, primarily comprising premium residential plots with extensive green cover and forest-themed amenities. “North Bengaluru, especially the Devanahalli-IVC Road belt, is witnessing strong demand from end-users and investors due to the airport expansion, upcoming metro, and IT-BT corridor growth,” said Gaurav Pandey, MD & CEO, Godrej Properties. The company expects to achieve a booking value of Rs 3,000–3,500 crore over the next 3–4 years, with an average realisation of Rs 10,000–12,000 per sq ft.

This marks GPL’s third major plotted development in Bengaluru in 2025, following Godrej Woodscapes (Whitefield) and Godrej Park Retreat Phase II (East Bengaluru). The company has already sold over Rs 5,000 crore worth of plotted inventory in the city this fiscal. Bengaluru continues to contribute over 35% of GPL’s total sales, with H1 FY26 bookings crossing Rs 6,200 crore.

With a strong launch pipeline of 12–15 million sq ft across key cities in H2 FY26, Godrej Properties remains on track to surpass its Rs 20,000 crore annual booking guidance. Shares rose 2.4% to Rs 3,085 on BSE post the announcement.

# सऊदी की खदानों में वेदांता की एंट्री: विजन 2030 पर 2 अरब डॉलर का भरोसा

## $2 अरब का खनन-प्रसंस्करण निवेश, जाबल सयिद में पहली खदान; विजन 2030 के साथ साझेदारी, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में मजबूती

**मुंबई:** भारत की प्रमुख खनन कंपनी वेदांता लिमिटेड सऊदी अरब के विशाल आर्थिक परिवर्तन योजना पर भारी दांव लगा रही है। कंपनी सोने और तांबे के नए खनन-प्रसंस्करण प्रोजेक्ट्स के लिए निवेश बढ़ाने की तैयारी में है, जो सऊदी के विजन 2030 को समर्थन देगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, वेदांता के तांबा और निकल प्रमुख पुनीत खुराना ने कहा, हम भारत में धातु मूल्य श्रृंखला विकसित कर चुके हैं, अब सऊदी के लिए भी यही करेंगे। कंपनी जनवरी के मध्य तक जाबल सयिद बेल्ट में पहली खदान के लिए अनुबंध जारी करेगी, जो 6-8 महीनों में खुदाई शुरू कर देगी।

वेदांता ने पहले ही सऊदी में $2 अरब (लगभग 16,800 करोड़ रुपये) निवेश का समझौता किया है, जिसमें तांबा प्रसंस्करण इकाइयां शामिल हैं। सितंबर में तांबा रॉड प्लांट का निर्माण शुरू हुआ, जो 2026 में उत्पादन देगा, और 2028 तक स्मेल्टर शुरू होगा। अनिल अग्रवाल नियंत्रित कंपनी ने सऊदी के मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड मिनरल रिसोर्सेज से लाइसेंस प्राप्त किया है।

सऊदी का अनुमान है कि उसके पास $1.3 ट्रिलियन के अकटेप्ड खनिज भंडार हैं, जिसमें तांबा, सोना और दुर्लभ मिट्टी शामिल हैं।

यह निवेश सऊदी के तेल-निर्भर अर्थव्यवस्था को विविधीकृत करने का प्रयास है, जहां खनन क्षेत्र का GDP योगदान $17 अरब से $64 अरब तक ले जाने का लक्ष्य है। वेदांता के CEO क्रिस ग्रिफिथ ने कहा, तांबे की मांग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वैश्विक तांबा मांग 2040 तक 40% बढ़ेगी, जो EV, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रेरित है। सऊदी का $2.5 ट्रिलियन खनिज धनअनलॉक करने का प्लान विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रहा है।

चीन की माइनिंग भी स्थानीय साझेदारी से खोज बढ़ा रही है, जो 5 वर्षों में तांबा-स्वर्ण उत्पादन शुरू करेगी। वेदांता का यह कदम भारत-सऊदी आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में सऊदी की भूमिका बढ़ेगी। वेदांता के शेयर 1.5% चढ़े। यह निवेश खनन क्षेत्र में नई संभावनाएं खोलेगा।

# राउरकेला स्टील प्लांट का विस्तार: स्टील मंत्री ने 9.8 MTPA क्षमता बढ़ाने की योजना की घोषणा की

## 30,000 करोड़ के निवेश से 2030 तक दोगुना उत्पादन, रक्षा-ऑटो सेक्टर को बल; केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने आधुनिक सुविधा का उद्घाटन किया

स्टील एवं भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के राउरकेला स्टील प्लांट (RSP) की क्षमता 9.8 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) तक बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। मंगलवार को प्लांट में आधुनिक स्टील मेकिंग सुविधा का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि यह विस्तार रक्षा, तेल-गैस और ऑटोमोबाइल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मजबूत करेगा। वर्तमान में RSP की क्षमता 4.4 MTPA है, जिसे 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य है। इस पर लगभग 30,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा।

कुमारस्वामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्टील नीति का उद्देश्य 2030- 31 तक भारत की स्टील क्षमता 300 MTPA तक ले जाना है।

RSP का विस्तार आयात निर्भरता कम करेगा और विशेष स्टील उत्पादन को बढ़ावा देगा। उन्होंने 1 MTPA स्लैब कैस्टर का उद्घाटन किया, जो 1,100 करोड़ की लागत से बना है। इसके अलावा, कोक ओवन बैटरी और पेलेट प्लांट के निर्माण की प्रगति का निरीक्षण किया। ओडिशा के CM ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। RSP, जो 1950 के दशक में जर्मन सहयोग से स्थापित भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का स्टील प्लांट है, अब 1959 से सक्रिय है। विस्तार से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, MSME को अवसर और सामुदायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। SAIL की कुल क्षमता 20.3 MTPA है, जिसमें RSP का योगदान 4.4 MTPA है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना पूर्वी भारत को स्टील हब बनाएगी। शेयर बाजार में SAIL के शेयर 0.63% चढ़कर 139.78 रुपये पर बंद हुए। यह कदम आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेगा।

# सेमीकंडक्टर क्रांति: 10 अरब डॉलर के बूस्ट के साथ 2032 तक वैश्विक दिग्गजों को चुनौती देने की तैयारी

## वैष्णव बोले- अगले 7 वर्षों में पारिस्थितिकी तंत्र विकसित, माइक्रॉन-टाटा प्लांट्स से उत्पादन शुरू; 2030 तक 10% वैश्विक बाजार हिस्सेदारी

**नई दिल्ली:** भारत 2032 तक चिप निर्माण में अमेरिका और चीन के बराबर पहुंचने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में कहा, 2031-32 तक हम उन देशों के समकक्ष होंगे, जहां आज वे हैं। तब दौड़ बराबरी की होगी।" 10 अरब डॉलर (लगभग 84,000 करोड़ रुपये) के सेमीकॉन्डक्टर पुश ने ब्लूप्रिंट से क्रियान्वयन तक की गति बढ़ाई है।

वैष्णव ने बताया कि तीन चिप सुविधाएं अगले वर्ष की शुरुआत में व्यावसायिक उत्पादन शुरू करेंगी। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी गुजरात में टेस्टिंग-पैकेजिंग प्लांट स्थापित कर रही है, जबकि टाटा ग्रुप गुजरात में पहला 12-इंच वाफर फैब ला रहा है। 2022 में 26.3 अरब डॉलर का बाजार 2032 तक 271.9 अरब डॉलर पहुंचेगा। PLI स्कीम के तहत 76,000 करोड़ का प्रोत्साहन दिया गया, जिसमें कंपाउंड सेमीकॉन्डक्टर, सेंसर और असेंबली-टेस्टिंग यूनिट्स शामिल हैं।

चीन प्लस वन रणनीति में भारत वैकल्पिक केंद्र बन रहा है। हालांकि, ताइवान-दक्षिण कोरिया, अमेरिका-चीन-जापान से पीछे हैं, जो सैकड़ों अरब डॉलर निवेश कर रहे हैं। वैष्णव ने कहा, हमारा डिजाइन इकोसिस्टम मजबूत है, इंजीनियरिंग टैलेंट गहरा। 2030 तक 110 अरब डॉलर का बाजार लक्ष्य है।

विशेषज्ञों का मानना है कि 10% वैश्विक हिस्सेदारी से आयात निर्भरता कम होगी। 2022 में 24 अरब डॉलर आयात हुआ। गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु जैसे राज्य नीतियां बना रहे हैं। यह पुश AI, IoT, 5G और EV के लिए महत्वपूर्ण है। शेयर बाजार में सेमीकॉन्डक्टर स्टॉक्स 2% चढ़े। यह कदम डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करेगा।

# WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

**Anil Bhardwaj**
Technical Head
anil.stockcare@gmail.com

AII level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is TRIGGER POINT for buy/sell Based on the price range of the previous Month, R1: Resistance one: 1st Resistance over PP; R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1; S1: Support one: 1st support after PP; S2: Support Two: 2nd support after S1

• As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and 1st target would be R1
• If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1
• If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
• Similarly, if price goes below PP the trader should SELL price below PP as stop loss and the first target would be S1,
• If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1,
• If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

| Stock name | closing Rate | R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY | 26068 | 26646 | 26446 | 26257 | 26057 | 25868 | 25668 | 25479 |
| BANK NIFTY | 58868 | 60143 | 59790 | 59329 | 58976 | 58515 | 58162 | 57701 |
| SENSEX | 85232 | 87113 | 86456 | 85844 | 85187 | 84575 | 83918 | 83306 |
| FINNIFTY | 27566 | 28297 | 28099 | 27833 | 27635 | 27369 | 27171 | 26905 |
| MIDCAP | 13851 | 14244 | 14158 | 14005 | 13919 | 13766 | 13680 | 13527 |
| ACC | 1828 | 1894 | 1879 | 1854 | 1839 | 1814 | 1799 | 1774 |
| AXISBANK | 1275 | 1340 | 1314 | 1294 | 1268 | 1248 | 1222 | 1202 |
| ABCAPITAL | 325 | 346 | 342 | 333 | 329 | 320 | 316 | 307 |
| BHARTIARTL | 2168 | 2269 | 2222 | 2195 | 2148 | 2121 | 2074 | 2047 |
| BHEL | 283 | 301 | 296 | 290 | 285 | 279 | 274 | 268 |
| BIOCON | 397 | 452 | 438 | 418 | 404 | 384 | 370 | 350 |
| CDSL | 1610 | 1739 | 1707 | 1658 | 1626 | 1577 | 1545 | 1496 |
| DATAPATTERN | 3024 | 3355 | 3283 | 3154 | 3082 | 2953 | 2881 | 2752 |
| ESCORTS | 3601 | 3798 | 3734 | 3668 | 3604 | 3538 | 3474 | 3408 |
| EICHERMOTOR | 7139 | 7866 | 7536 | 7337 | 7007 | 6808 | 6478 | 6279 |
| FEDERAL BANK | 244 | 264 | 257 | 250 | 243 | 236 | 229 | 222 |
| GRINFRAPOJECT | 1094 | 1208 | 1176 | 1135 | 1103 | 1062 | 1030 | 989 |
| HDFCBANK | 998 | 1038 | 1025 | 1011 | 998 | 984 | 971 | 957 |
| HCLTECH | 1609 | 1740 | 1704 | 1657 | 1621 | 1574 | 1538 | 1491 |
| HINDUNILVR | 2440 | 2522 | 2491 | 2465 | 2434 | 2408 | 2377 | 2351 |
| HAL | 4594 | 5041 | 4949 | 4771 | 4679 | 4501 | 4409 | 4231 |
| HYUNDAI | 2333 | 2622 | 2541 | 2437 | 2356 | 2252 | 2171 | 2067 |
| IOC | 167 | 180 | 177 | 172 | 169 | 164 | 161 | 156 |
| ICICIBANK | 1369 | 1406 | 1397 | 1383 | 1374 | 1360 | 1351 | 1337 |
| INFY | 1544 | 1644 | 1599 | 1572 | 1527 | 1500 | 1455 | 1428 |
| ITC | 408 | 418 | 414 | 411 | 407 | 404 | 400 | 397 |
| KOTAKBNK | 2087 | 2151 | 2135 | 2111 | 2095 | 2071 | 2055 | 2031 |
| LICHOUSING | 547 | 594 | 584 | 565 | 555 | 536 | 526 | 507 |
| LT | 4023 | 4138 | 4098 | 4060 | 4020 | 3982 | 3942 | 3904 |
| LUPIN | 2031 | 2119 | 2098 | 2064 | 2043 | 2009 | 1988 | 1954 |
| MARUTI | 16009 | 16761 | 16456 | 16232 | 15927 | 15703 | 15398 | 15174 |
| M&M | 3747 | 3906 | 3842 | 3795 | 3731 | 3684 | 3620 | 3573 |
| MGL | 1215 | 1296 | 1279 | 1247 | 1230 | 1198 | 1181 | 1149 |
| MAZGAONDOC | 2742 | 2925 | 2887 | 2814 | 2776 | 2703 | 2665 | 2592 |
| PFC | 370 | 388 | 384 | 377 | 373 | 366 | 362 | 355 |
| RECLTD | 358 | 369 | 367 | 362 | 360 | 355 | 353 | 348 |
| RELIANCE | 1544 | 1611 | 1585 | 1564 | 1538 | 1517 | 1491 | 1470 |
| SBIN | 973 | 1000 | 993 | 983 | 976 | 966 | 959 | 949 |
| SUNPHARMA | 1783 | 1845 | 1818 | 1801 | 1774 | 1757 | 1730 | 1713 |
| SHRIRAMFINANCE | 823 | 857 | 844 | 834 | 821 | 811 | 798 | 788 |
| TITAN | 3902 | 4082 | 4019 | 3960 | 3897 | 3838 | 3775 | 3716 |
| TCS | 3150 | 3278 | 3223 | 3187 | 3132 | 3096 | 3041 | 3005 |
| TATAMOTORS | 363 | 398 | 389 | 376 | 367 | 354 | 345 | 332 |
| UPL | 749 | 793 | 784 | 766 | 757 | 739 | 730 | 712 |
| VALIENT | 267 | 312 | 302 | 285 | 275 | 258 | 248 | 231 |
| WIPRO | 244 | 255 | 251 | 248 | 244 | 241 | 237 | 234 |

## इंफोसिस का 18,000 करोड़ का रिकॉर्ड बायबैक: अतिरिक्त कैश का उपयोग, शेयरधारकों को लाभ

### 1,800 रुपये प्रति शेयर पर 1 करोड़ शेयर खरीद का ऑफर, प्रमोटर्स भाग नहीं लेंगे; कल 20 नवंबर से शुरू, 26 तक चलेगा

भारत की प्रमुख आईटी कंपनी इंफोसिस लिमिटेड ने 18,000 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड शेयर बायबैक ऑफर लॉन्च किया है, जो कंपनी के पास जमा अतिरिक्त कैश का उपयोग करने का प्रयास है। कंपनी ने मंगलवार को रेगुलेटरी फाइलिंग में घोषणा की कि 20 नवंबर से 26 नवंबर तक चलने वाले इस बायबैक में 1 करोड़ शेयर (कुल इक्विटी का 2.41%) 1,800 रुपये प्रति शेयर पर खरीदे जाएंगे। यह कंपनी का पांचवां बड़ा बायबैक है, जो FY25 में फ्री कैश फ्लो का 85% शेयरधारकों को लौटाने की कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी का हिस्सा है। कंपनी के पास FY25 के अंत तक 13,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कैश था, जो FY26 में 15,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। बायबैक से इक्विटी बेस कम होगा, जिससे प्रति शेयर आय (EPS) बढ़ेगी और शेयरधारक मूल्य मजबूत होगा। रिकॉर्ड डेट 14 नवंबर 2025 है, जिसमें छोटे शेयरधारकों (<2 लाख रुपये निवेश) के लिए 15% आरक्षण है। एंटाइटलमेंट रेशियो रिजर्व्ड कैटेगरी में 2:11 और जनरल में 17:706 है। प्रमोटर्स नंदन नीलेकणि, सुधा मूर्ति समेत 13.05% हिस्सेदारी वाले, भाग नहीं लेंगे, जिससे रिटेल निवेशकों को अधिक लाभ मिलेगा।

बायबैक टेंडर ऑफर रूट से NSE और BSE पर होगा। FY25 में कंपनी का राजस्व 5% बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपये और PAT 2% बढ़कर 26,000 करोड़ रुपये रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम शेयरधारकों का विश्वास बढ़ाएगा। शेयर 1,527 रुपये के ऊंचे स्तर पर पहुंचे। यह बायबैक आईटी सेक्टर की स्थिरता को दर्शाता है।

*Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.*

प्रकाशक एवं मुद्रक: प्रदीप कारबेलकर, सी-101, नेहरू नगर स्वत्वाधिकार द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज प्रा.लि., इ-4, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश 462016, से प्रकाशित एवं DigitalLok, सागर हाई स्ट्रीट, अयोध्या बायपास रोड, डी मार्ट के पास, भोपाल, (म.प्र.) - 462010। संपादक: प्रदीप कारबेलकर (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)। फोन: +9198262 23075 वेबसाइट: www.investmentavenues.in